

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 609

दिनांक 03 फरवरी, 2026

स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जलवायु-प्रतिरोधी कृषि पद्धतियाँ

609. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान (आईटीके) आधारित जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों का रख-रखाव और दस्तावेजीकरण करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ऐसी आईटीके-आधारित पद्धतियों की पहचान, सत्यापन और प्रचार के लिए नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सहयोग करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने मशीनरी संचालन और रख-रखाव में प्रशिक्षण सहित बड़े पैमाने पर जलवायु अनुकूल कृषि विस्तार सेवाओं को प्रदान करने में राज्य स्तर पर क्षमता अंतराल का आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और
- (घ) क्या जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने या विकसित करने वाले किसानों को ऐसे नवाचारों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए कोई वित्तीय या संस्थागत प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  
(श्री भागीरथ चौधरी )

(क) एवं ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अपनी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP) के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों से जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों सहित लगभग 5000 स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (ITK) को संकलित किया है और इसे 04 खंडों में शीर्षक "इन्वेंट्री ऑफ इंडीजीनियस टेक्नीकल नॉलेज (ITK) इन एग्रीकल्चर" (<https://icar.org.in/sites/default/files/2025-10/ICAR%20Insights%20Outcomes%20Booklet%20%28English%29.pdf>) में दस्तावेजी रूप दिया है। इन आईटीके का संकलन स्वैच्छिक डिस्कलोजर के माध्यम से प्रारंभिक स्रोत से किया गया है और यह पुस्तकों, पत्रिकाओं, थीसिस आदि के रूप में साहित्य के तौर पर उपलब्ध है ताकि इसे एक स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके। कुछ फसल आधारित आईटीके में शामिल है : जोखिम को न्यूनतम करने के लिए संवर्धन पद्धतियाँ, चावल की शुष्क बीजाई, मिट्टी संरक्षण के लिए वर्षा आधारित पारंपरिक खेती में पास-पास उगने वाली फसलों की खेती, रागी (मंडुआ) में पगड़ी (Pagadi) रोपण विधि, अधिक तीव्र वर्षा से पौधों को होने वाले

नुकसान से बचाने हेतु हस्त नक्षत्र के 'लोखंडी चरण' के पहले तीन दिनों के बाद रबी ज्वार की बुवाई, वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल जमाव सुनिश्चित करने के लिए अगेती बीजाई, सूखी बीजाई और रोपाई, मक्का में नमी संरक्षण के लिए खाखरा मल्लिग, जैविक पदार्थों का उपयोग तथा दीमक नियंत्रण। हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) के दौरान कुल 110 किसान प्रेरित नवाचारों की पहचान की, उन्हें संकलित किया और उन्हें दस्तावेजी रूप दिया है। इस अभियान को 29 मई से 12 जून, 2025 की अवधि में प्रगतिशील किसानों, नव-प्रवर्तकों, कृषि उद्यमियों, एफपीओ, एसएचजी, राज्य विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते हुए आयोजित किया गया था। दर्ज किए गए कुछ नवाचारों में शामिल हैं: शहरी छतों पर जैविक खाद्य उत्पादन, शुष्क भूमि के लिए मिट्टी को भुरभुरा करने वाले रोलर का अनुकूलन, सौर ऊर्जा संचालित स्वचालित हाइड्रोपोनिक प्रणाली, सूखा तैयारी के लिए सामुदायिक आधारित चारा बैंक की अभिनव व्यवस्था, 'अमूल्य अमृत' - किसान द्वारा विकसित जैविक नाशीजीव एवं रोग नियंत्रण घोल, धान कटाई के बाद खाली खेतों में बिना जुताई (ज़ीरो टिलेज) से मटर एवं पत्ता गोभीवर्गीय फसलों की खेती, तथा सब्जियों में देशी मल्लिग द्वारा जल संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण। (<https://atarijabalpur.org/Publication.html>)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से, जिनमें से कुछ का संचालन सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किया जाता है, ऐसी आईटीके (पारंपरिक ज्ञान) आधारित पद्धतियों का सत्यापन और प्रसार किया है।

**(ग) :** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अग्रणी परियोजना नामतः राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA) के अंतर्गत आईपीसीसी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए जलवायु-परिवर्तन में भारतीय कृषि का जोखिम एवं संवेदनशीलता मूल्यांकन किया गया और अत्यधिक तथा उच्च जोखिम वाले कुल 301 जिलों की पहचान की गई। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निम्न परियोजना देशभर के कुल 151 जोखिम संवेदनशील जिलों में चलाई जा रही है। प्रत्येक गाँव में कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) ने सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के माध्यम से तकनीकी आवश्यकताओं की कमियों का आकलन किया और क्रियान्वयन हेतु स्थान-विशिष्ट, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी। पिछले 15 वर्षों में, निम्न परियोजना के तहत अंगीकृत किए गए गाँवों में किसानों की सहभागी पद्धति से कृषि यंत्रों के संचालन और रखरखाव सहित जलवायु-अनुकूल कृषि के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 25,000 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनसे 7.5 लाख किसान एवं अन्य हितधारक लाभान्वित हुए।

**(घ) :** जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और उनका उन्नयन करने में किसानों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (NMSA) को लागू किया गया है। यह मिशन जलवायु-परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही योजना (NAPCC) के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (NMSA) में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं: बारानी क्षेत्रफल विकास (RAD); ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM); तथा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM)। भारत सरकार द्वारा जलवायु-परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (NMSA) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निम्न परियोजना के अंतर्गत अंगीकृत किए गए गाँवों में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के साथ कस्टम हायरिंग केंद्रों, बीज एवं चारा बैंकों, सामुदायिक धान नर्सरियों, गाँव जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियों जैसे संस्थागत हस्तक्षेप किए गए हैं ताकि गाँव में अनुकूल पद्धतियों का विस्तार किया जा सके।

\*\*\*\*\*